Thirteenth Loksabha

Session : 13
Date : 06-08-2003

Participants : Singh Shri Maheshwar

Title: Need to review the provision of 'Food Parks' with a view to provide benefit to small farmers particularly in hilly areas.

14.01 hrs.

(The Lok Sabha reassembled after lunch at one minute past

fourteen of the Clock)

(MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने एवं किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने की दृटि से फूड पार्क की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना बनाई थी। पहले तो इस योजना का प्रचार बहुत कम था कि लाभार्थियों को इसका पता ही देर से लगा और जब लाभार्थियों ने अपने आवेदन दिये, तो नौंवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। फलस्वरूप जिन लोगों ने मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किये, वे अधर में लटक गये और 10वीं पंचवर्षीय योजना में फूड पार्क स्थापित करने हेतु सबसिडी घटाकर केवल 30 प्रतिशत कर दी गई है जब कि पहले अधिकतम 4 करोड़ रुपये तक सबसिडी दी जा सकती थी। दूसरे, इस हेतु भूमि की आवश्यकता प्रोजैक्ट रिपोर्ट तथा अधिकारियों के विवेक पर निर्भर थी, परन्तु अब भूमि की न्यूनतम आवश्यकता 3 एकड कर दी गई। ऐसा करने से स्पट है कि छोटे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे। विशेाकर पहाड़ी प्र ाान्तों में किसानों के पास 30 एकड़ भूमि का होना कठिन है। इसलिये मेरा आग्रह है कि जिन प्रकरणों हेतु मंत्रालय ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दी है और औपचारिकतायें पूर्ण न होने से उनके प्रकरल लम्बित पड़े हैं, उन्हें अविलम्ब स्वीकृति प्र ादान की जाये। ऐसे प्रकरण मेरी जानकारी के अनुसार तीन हैं। इसके अतिरिक्त 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान किये गये हैं, उन पर सरकार पुनर्विचार करे ताकि छोटे किसान भी लाभान्वित हो सकें ।